RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 01 JANUARY TO 08 JANUARY 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 19 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

ONGC की छोटी फील्ड्स के लिए बिड देने की डेडलाइन बढ़ी
Page 2

फार्मा सेक्टर के लिए आ सकती है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम
Page 4

Jawa Perak की बुकिंग शुरू, 10 हजार में करें बुक
Page 7

editoria!

बेरोजगारी की चिंता

बेरोजगारी दूर न होने से देश के लोगों में चिंता बढ़ रही है। खासकर शहर के लोग बेरोजगारी को लेकर सबसे ज्यादा फिक्रमंद हैं। शुक्रवार को जारी मार्केट रिसर्च कंपनी 'इप्सॉस' की रिपोर्ट 'वॉट वरीज द वर्ल्ड' के अनुसार 46 फीसदी शहरी भारतीय बेरोजगारी के मुद्दे को सबसे बड़ी चिंता मानते हैं। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में 3 प्रतिशत शहरी भारतीयों की फिक्र बेरोजगारी को लेकर बढ़ गई। दरअसल इप्सॉस हर महीने 28 देशों में यह सर्वे कराती है, जिसका मकसद लोगों की संतुष्टि और असंतुष्टि का स्तर जानना हुआ करता है। इस सर्वे में हमारे लिए एक बात जरूर आश्वस्त करने वाली है कि 69 फीसदी शहरी भारतीय मानते हैं कि देश सही रास्ते पर जा रहा है। मतलब यह कि वे देश की वर्तमान हालत से संतुष्ट हैं। उन्हें वित्तीय और राजनीतिक भ्रष्टाचार, अपराध और हिंसा, गरीबी, सामाजिक असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे परेशान कर रहे हैं, मगर वे कुल मिलाकर आशावादी हैं। सर्वेक्षण का संदेश साफ है कि बेरोजगारी ही भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उसे इस समस्या को अपने अजेंडे पर सबसे ऊपर रखना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार इस पर भारी असमंजस में दिखती है। एक तरफ खुद श्रम मंत्रालय बताता है कि देश में 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1 फीसदी रही जो 45 साल में सबसे ज्यादा थी, लेकिन दूसरी तरफ कई अवसरों पर सरकार के नुमाइंदे इसे नकारते भी रहते हैं। पिछले दिनों श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में इस बात से ही इनकार किया कि रोजगार के अवसरों में कमी हुई है। जबकि कई स्रोतों से यह बात सामने आई है कि देश में आर्थिक सुस्ती के कारण बीते कुछ महीनों में ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2 लाख से अधिक नौकरियां चली गई हैं। टेक्सटाइल और रियल एस्टेट सेक्टर में भी नौकरियां कम हुई हैं। आज ज्यादातर विदेशी या भारतीय कंपनियां कौशल पर बहुत ज्यादा जोर दे रही हैं, लेकिन कुशल लोगों की अब भी भारी कमी है। पिछले कुछ वर्षों में उन युवाओं की भारी फौज देश में तैयार हो गई है, जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी डिग्री हासिल की है, लेकिन उनमें वैसे किसी कौशल का अभाव है, जो उन्हें कोई काम दिला सके। ऐसे करीब 47 फीसदी शिक्षित युवा हैं, जो किसी भी नौकरी के लायक नहीं। कौशल उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई योजना स्किल इंडिया का लाभ बड़े पैमाने पर अभी भी नहीं पहुंच पाया है। रोजगार उपलब्ध कराने में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान होता है, पर हमारे देश में इस सेक्टर की बजाय सर्विस सेक्टर का ज्यादा विकास हुआ है, जिनमें रोजगार की गुंजाइश कम है। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। ऐसी नीतियां बनानी होंगी कि उद्योगपति श्रम उन्मुख उत्पादों के क्षेत्र में आगे आ सकें। पर यह सब तभी हो सकेगा जब सरकार रोजगार बढ़ाने के लक्ष्य को अपने अजेंडे में सबसे ऊपर रखे।

लगातार दूसरे महीने 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा GST रेवेन्यू कलेक्शन

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

जीएसटी कलेक्शन (उएऊ म्दत्तमूदह) के मोर्चे पर केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, लगातार दूसरे महीने यानी दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है। नवंबर महीने में कुल 1,03,492 करोड़ रुपये की जीएसटी वसूली हुई थी। वहीं, दिसंबर में ये आंकड़ा 1,03,000 करोड़ रुपये रहा है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से आंकड़े जारी नहीं हुए है। अगर अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के आंकड़ों पर नज़र डालें तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तीन ऐसे महीने रहे हैं। जब जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपये के नीचे रहा है। वहीं, मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल महीने के दौरान जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा 1,13,865 करोड़ रुपये रहा था। आपको बता दें कि जुलाई 2019 में जीएसटी लागू किए जाने के बाद यह 9वां ऐसा महीना है, जब जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य के पार पहुंचा है।

फरवरी 2020 से डिजिटल पेमेंट न लेने पर फर्मों- दुकानों पर लग सकता है जुर्माना

नई दिल्ली। एजेंसी

नए साल पर व्यावसायिक फर्म,कंपनियां और दुकानों जिनका सालाना टर्नओवर 50 करोड़ है, उनको डिजिटल पेमेंट न लेना मंहगा पड़ सकता है। फरवरी से ऐसा न करने पर सरकार ने भारी जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। डिजिटल पेमेंट्स न लेने पर ऐसी कंपनियों को 1 फरवरी से प्रत्येक दिन के हिसाब से 5000 रू तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने स्पष्ट करते हुए कहा कि इस फैसले को लागू करने का मकसद व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट के लिए सिस्टम इंस्टॉल करने का पर्याप्त समय देना है। सीबीडीटी ने आगे कहा कि वित्त अधिनियम के खंड 271DB के तहत ऐसे व्यक्ति को न छोड़ा जाए जिसने 31 जनवरी 2020 या उसके पहले डिजिटल पेमेंट के लिए सिस्टम इंस्टॉल न किया हो।रूपे और यूपीआई फिलहाल डिजिटल पेमेंट के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं जिसमें मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगता है। एमडीआर डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रतिशत होता है जो मर्चेंट बैंक को अदा करता है। यह लागत मूलतः ग्राहक के पास जाती है।

गौरतलब है कि जुलाई में बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भीम यूपीआई, यूपीआई-क्यूआर कोड, आधार पे, और कुछ डेबिट कार्ड को लो कॉस्ट डिजिटल पेमेंट मोड में सूचीबद्ध किया था। इसका मकसद कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना था।

रेलवे ने आरपीएफ का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा किया

नयी दिल्ली। एजेंसी

रेलवे ने अपने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया है। सोमवार को जारी एक आदेश के मुताबिक, मंत्रालय ने आरपीएफ को संगठित ग्रुप ए का दर्जा दिया है और इसका नाम बदल दिया है। आदेश में कहा गया है, " माननीय अदालत के आदेश के बाद कैबिनेट के निर्णय के मद्देनजर आरपीएफ को संगठित समूह ए (ओजीएएस) का दर्जा दिया जाता है और सूचित किया जाता है कि आरपीएफ को भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के तौर पर जाना जाएगा।"

बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 19 रुपये महंगा, विमान ईंधन का दाम भी बढ़ा

नयी दिल्ली। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी के चलते विमान ईंधन (एटीएफ) के दाम में बुधवार को 2.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई। बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर भी 19 रुपये महंगा हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की मूल्य के बारे में जारी अधिसूचना के अनुसार , दिल्ली में विमान ईंधन की कीमत 1,637.25 रुपये किलोलीटर यानी 2.6 प्रतिशत बढ़कर 64,323.76 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी की वजह से दरों में लगातार दूसरे महीने वृद्धि की गई है। इससे पहले एक दिसंबर को एटीएफ के दामों में मामूली 13.88 रुपये किलोलीटर की वृद्धि की गई थी। इस वृद्धि का बोझ पहले से नकदी संकट का सामना कर रही एयरलाइन कंपनियों पर पड़ेगा। इसके अलावा, तेल विपणन कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर का दाम भी 695 रुपये से बढ़ाकर 714 रुपये कर दिया है। यह लगातार पांचवां महीना है जब रसोई गैस के दाम में वृद्धि की गई है। रसोई गैस की कीमत 2019 से बढ़ाई जा रही है। पिछले पांच महीनों में बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस के दाम 139.50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़े हैं।

तेल, गैस क्षेत्र के नियामक ने गैस मांग, बुनियादी ढांचा आकलन के लिये आईसीएफ की सेवायें ली

नयी दिल्ली। एजेंसी

तेल एवं गैस नियामक नियामक पीएनजीआरबी ने देश में प्राकृतिक गैस की मांग और इस क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ाने के लिये जरूरी बुनियादी ढांचे के बारे में आकलन करने के वास्ते वैश्विक परामर्श कंपनी आईसीएफ की सेवायें ली हैं। पीएनजीआरबी के चेयरमैन दिनेश के सर्राफ ने यह जानकारी दी। पेट्रोल, डीजल और कोयला जैसे अन्य ईंधन के मुकाबले प्राकृतिक गैस अधिक पर्यावरण अनुकूल है क्योंकि इसमें कार्बन उत्सर्जन की मात्रा काफी कम है। इसके बावजूद देश में कुल ऊर्जा खपत में इसकी हिस्सेदारी केवल 6.2 प्रतिशत है। वहीं वैश्विक औसत 24 प्रतिशत है।पर्यावरण अनुकूल ईंधन के कम उपयोग का एक प्रमुख कारण अपर्याप्त गैस उत्पादन तथा बुनियादी ढांचा खासकर उपयोगकर्ताओं तक ईंधन पहुंचाने के लिये पाइपलाइन की उपलब्धता का अभाव है।

सर्राफ ने कहा, ''हमने मांग और बुनियादी ढांचा के व्यापक आकलन के लिये आईसीएफ की सेवायें ली है।'' रिपोर्ट 2020 के मध्य तक आने की उम्मीद है।भारत ने 2030 तक कुल ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2018-19 में 16.6 करोड़ घन मीटर प्रतिदिन गैस की खपत हुई। यह खपत मुख्य रूप से पश्चिमी और उत्तरी भारत में हुई क्योंकि पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र बहुत कम पाइपलाइन ग्रिड से जुड़े हैं। खपत मांग को प्रतिबिंबित नहीं करती क्योंकि कुछ मांग केंद्रों पर गैस की पहुंच ही नहीं है।पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामकीय बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने 2012-13 में मांग का आकलन किया था। उसमें कहा गया था कि गैस मांग संचयी रूप से सालाना 6.8 प्रतिशत की दर से बढ़कर 2029-30 तक 74.6 करोड़ घन मीटर प्रतिदिन तक पहुंच जाने का अनुमान है। सर्राफ ने कहा, ''हमने गुजरात मॉडल का अध्ययन किया है जहां कुल ईंधन खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी देश में सर्वाधिक 25-26 प्रतिशत है।

एक प्रमुख विशेषता जो हमने पायी वह यह कि राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राज्य में व्यापक स्तर पर गैस पाइपलाइन का जाल बिछाया गया।''उन्होंने कहा, ''आईसीएफ की रिपोर्ट से हमें बेहतर तरीके से योजना बनाने में मदद मिलेगी... हमारे पास मांग के बारे में व्यापक आकलन होगा और पाइपलाइन की जरूरत वाले मार्गों के बारे में जानकारी होगी, तब हम ऐसी लाइन के निर्माण के लिये बोलियां आमंत्रित कर सकते हैं।'' अध्ययन से एलएनजी आयात टर्मिनल के बेहतर स्थानों का भी पता चलेगा। इससे संबंधित उद्योग परियोजनाओं की योजना उसके अनुसार बना सकते हैं।

नए साल के पहले दिन रुपये में शुरुआती कारोबार में मजबूती

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

नए साल के पहले दिन रुपया बढ़त के साथ खुला और बुधवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले सात पैसे चढ़कर 71.29 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया। अमेरिका - चीन व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक रुख से निवेशकों की धारणा मजबूत हुई। मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और घरेलू शेयर बाजार की अच्छी शुरुआत से भी रुपये को समर्थन मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में , रुपया अमेरिकी मुद्रा की तुलना में बढ़त के साथ 71.30 रुपये प्रति डॉलर पर खुला और शुरुआती कारोबार में बढ़कर 71.29 रुपये पर पहुंच गया। यह पिछले कारोबार दिन के बंद से सात पैसे बढ़कर चल रहा था। रुपया मंगलवार को 71.36 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। कारोबारियों ने कहा कि अमेरिका - चीन व्यापार समझौते पर सकारात्मक रुख से रुपया को मजबूती मिली। अमेरिका और चीन के बीच एक नये आंशिक व्यापार समझौते पर अगले महीने के मध्य में हस्ताक्षर किए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगवालर को यह बात कही। अंतरराष्ट्रीय खनिज तेल बाजार में ब्रेंट कच्चा तेल का वायदा भाव 1 प्रतिशत गिरकर 66 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा था। शेयर बाजार के पास मौजूद आरंभिक आंकड़ों के मुताबिक , विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मंगलवार को शुद्ध रूप से 1,265.10 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

भारत के लिये 2020 में पांच प्रतिशत वृद्धि दर हासिल करना होगा मुश्किल- अर्थशास्त्री स्टीव हंके

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत को 2020 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पांच प्रतिशत वृद्धि दर हासिल करने के लिए 'काफी मेहनत' करनी पड़ सकती है। प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव हंके ने यह राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली कुछ तिमाहियों में आर्थिक वृद्धि दर में काफी गिरावट आई है। इसकी प्रमुख वजह ऋण में कमी आना है जो चक्रीय समस्या है। हंके फिलहाल जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी (यूएसए) में एप्लायड इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत में ऋण की काफी तेज वृद्धि देखने को मिली, लेकिन आज स्थिति यह है कि गैर- निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बढ़ रही हैं। विशेषरूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का डूबा कर्ज बढ़ रहा है। हंके ने न्यूज एजेंसी से साक्षात्कार में कहा, ''भारत में सुस्ती की वजह ऋण संकुचन है, जो एक चक्रीय समस्या है। यह संरचनात्मक समस्या नहीं है। ऐसे में भारत को 2020 में पांच प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है।'' हंके ने इसके साथ कहा कि भारत पहले से काफी अधिक संरक्षणवाद से घिरा हुआ है। भारत को अभी तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था गिना जा रहा था। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 4.5 प्रतिशत रह गई है जो इसका छह साल का निचला स्तर है। हंके पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की आर्थिक सलाहकार परिषद में भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बड़े आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने में विफल रही है। हंके ने कहा कि मोदी सरकार की कड़े और जरूरी आर्थिक सुधारों में जरा भी रुचि नहीं है। इसके बजाय मोदी सरकार दो चीजों ..धर्म और जाति... जैसी अस्थिरता और संभावित रूप से विस्फोटक मुद्दों पर ध्यान दे रही है। अमेरिकी अर्थशास्त्री ने कहा, ''यह एक खतरनाक 'कॉकटेल' है। काफी लोगों का मानना है कि मोदी के शासनकाल में भारत पहले ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से बदलकर सबसे बड़े 'पुलिस स्टेट' में तब्दील हो रहा है। इस बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की प्रतिक्रिया जानने के लिये भेजे ई-मेल का कोई जवाब नहीं मिला।

ONGC की छोटी फील्ड्स के लिए बिड देने की डेडलाइन बढ़ी

नई दिल्ली। एजेंसी

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्प (ONGC) ने अपनी प्रॉडक्शन कर रही 64 छोटी फील्ड्स को ऑपरेट करने में दिलचस्पी रखने वाली प्राइवेट कंपनियों के लिए बिड देने की डेडलाइन 3 जनवरी तक बढ़ा दी है। बिड जून में मंगाई गई थी और इसके लिए डेडलाइन पहले 20 दिसंबर की थी। इन फील्डर्स में दिलचस्पी रखने वाली प्राइवेट कंपनियों की कई आशंकाओं को ONGC ने प्री-बिड मीटिंग में दूर किया है। हालांकि, अभी भी कुछ आशंकाएं बाकी हैं। नए टेंडर डॉक्यूमेंट के अनुसार, कॉन्ट्रैक्टर्स के पास अब परफॉर्मेंस बैंक गारंटी और फील्ड डिवेलपमेंट प्लान प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय होगा।

एक कॉन्ट्रैक्टर अब पूरी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी छोड़कर तीन वर्षों से पहले भी फील्ड से बाहर निकल सकेगा। पहले फील्ड से तीन वर्षों बाद ही निकलने का प्रोविजन था। ध्ऊ ने कुछ संभावित बिडर्स के भविष्य में बेसलाइन प्रॉडक्शन फोरकास्ट को एडजस्ट करने का निवेदन स्वीकार नहीं किया है। ONGC ने प्री-बिड मीटिंग में बताया, 'बेसलाइन प्रॉडक्शन का अनुमान गिरावट की पिछली दरों और फील्ड के वर्तमान प्रॉडक्शन के अनुसार लगाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार, बेसलाइन प्रॉडक्शन पर मोलभाव नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के दौरान इसे बरकरार रखना होगा।'

इसके अलावा ONGC ने संभावित बिडर्स की ओर से बेसलाइन प्रॉडक्शन में एक हिस्सेदारी लेने की मांग को भी स्वीकार नहीं किया है। प्राइवेट कंपनियों को सभी नई कॉस्ट का भार उठाना होगा, लेकिन उन्हें बेसलाइन प्रॉडक्शन से अधिक प्रॉडक्शन पर ही एक हिस्सेदारी मिलेगी। ONGC की छोटी फील्ड्स का मालिकाना हक प्राइवेट कंपनियों को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यह देश में इस तरह की पहली व्यवस्था है और इसमें कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। ध्ऊ के लिए एक बड़ी मुश्किल बड़ी संख्या में प्राइवेट ऑपरेटर्स क साथ कोऑर्डिनेट करने और अपने उन कर्मचारियों को दोबारा तैनात करने की होगी जो इन फील्ड्स से हटाए गए हैं। दुर्घटना होने की स्थिति में जिम्मेदारी तय करने पर विवाद हो सकता है। ध्ऊ के पास इन फील्ड्स की माइनिंग लीज होगी, जबकि प्राइवेट कंपनियों के पास फील्ड्स के ऑपरेशंस की जिम्मेदारी रहेगी। प्राइवेट ऑपरेटर्स उन फील्डर्स के लिए प्रोसेसिंग की व्यवस्था कर सकते हैं जहां ध्ऊ की मौजूदा प्रोसेसिंग कम पड़गी। इससे प्राइवेट ऑपरेटर्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। फील्ड का ऑपरेटर बदलने के साथ एक और चुनौती फील्ड में मौजूद इक्विपमेंट की सुरक्षा और स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ने की होगी। ध्ऊ की इन फील्ड्स के प्राइवेट कंपनियों के पास जाने से प्रॉडक्शन बढ़ने की उम्मीद है।

आयकर में राहत के लिये सभी की निगाहें सीतारमण के दूसरे आम बजट पर

नयी दिल्ली। एजेंसी

आयकर में राहत पाने के लिये आम करदाता की नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दूसरे आम बजट पर लगी हैं। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में छाई सुस्ती और कंपनी कर में की गई भारी कटौती को देखते हुये आयकर में कोई बड़ी राहत देना उनके लिये कड़ी चुनौती हो सकती है। सीतारमण को जुलाई, 2019 में पेश अपने पहले बजट में इस बात को लेकर काफी आलोचना सहनी पड़ी थी कि उन्होंने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिये कुछ खास नहीं किया। इसके बाद वित्त मंत्री ने सितंबर में कंपनियों के लिये कर में बड़ी कटौती की घोषणा कर सभी को हैरान कर दिया। कंपनी कर में की गई इस कटौती से केन्द्र सरकार के राजस्व में 1.45 लाख करोड़ रुपये की कमी आने का अनुमान लगाया गया। इसके साथ ही कई वस्तुओं पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की दरों में भी कमी की गई। आवास, इलेक्ट्रिक वाहन, होटल में ठहरने का किराया, हीरे के जॉबवर्क और घर से बाहर होने वाली कैटरिंग जैसी गतिविधियों पर जीएसटी में कमी की गई। कर दरों में की गई कटौती के साथ साथ ही कमजोर चाल से चल रही अर्थव्यवस्था में उपभोग में आती गिरावट, राजस्व संग्रह में सुस्ती के कारण बजट में तय राजस्व लक्ष्यों को हासिल करना वित्त मंत्री के समक्ष बड़ी चुनौती खड़ी कर रहा है।

आम नौकरीपेशा और सामान्य करदाता इन सब बातों को दरकिनार करते हुये केंद्र सरकार की दूसरी पारी में कर दरों में राहत की उम्मीद लगाये बैठा है। सरकार ने हालांकि आम नौकरीपेशा लोगों की पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आय को पहले ही करमुक्त कर दिया है। लेकिन कर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। मौजूदा स्लैब के मुताबिक ढाई लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं है जबकि 2.50 लाख से पांच लाख पर पांच प्रतिशत, पांच से 10 लाख रुपये की वार्षिक आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अधिक की कमाई पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लागू है। 60 साल के वरिष्ठ नागिरक और 80 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिये क्रमश तीन लाख और पांच लाख रुपये तक की आय कर मुक्त रखी गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि वित्त मंत्री को आयकर स्लैब में बदलाव करना चाहिये। पिछले कई सालों से इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को 2020- 21 का आम बजट पेश करेंगी। जीएसटी परिषद की चार बैठकों की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। इस तरह की आखिरी बैठक दिसंबर में हुई जिसमें आर्थिक सुस्ती के चलते राजस्व संग्रह में आ रही कमी पर गौर किया गया। इसी आर्थिक सुस्ती का परिणाम है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में छह साल के निम्न स्तर 4.5 प्रतिशत पर आ गई। इसके बाद सरकार ने अर्थव्यवस्था में गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये अनेक उपाय किये।

छह साल के निम्न स्तर पर पहुंच आर्थिक वृद्धि और 45 साल के उच्च स्तर पर पहुंची बेरोजगारी दर से जूझ रही सरकार ने पिछले साल सितंबर में कॉरपोरेट कर की दर को करीब 10 प्रतिशत घटाकर 25.17 प्रतिशत पर ला दिया। यह दर चीन और दक्षिण कोरिया जैसे एशिया से बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुये की गई है। नई विनिर्माण इकाइयों को निवेश के लिये आकर्षित करने के लिये 15 प्रतिशत कर की दर तय की गई। वित्त मंत्री ने कंपनियों के लिये कॉरपोरेट कर की मूल दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया, अधिभार और उपकर मिलाकर यह दर 25.17 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। इसके साथ ही एक अक्टूबर 2019 के बाद विनिर्माण क्षेत्र में उतरने वाली और 31 मार्च, 2023 से पहले कामकाज शुरू करने वाली नई कंपनियों के लिये कंपनी कर की दर घटाकर 15 प्रतिशत कर दी गई। यहां यह उल्लेखनीय है कि चीन, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया की कंपनियां अपने मुनाफे पर 25 प्रतिशत की दर से कर देती हैं। वहीं मलेशिया की कंपनियां 24 प्रतिशत की दर से कर भुगतान करती हैं।

एशिया क्षेत्र में केवल जापान ही ऐसा देश है जहां कंपनियों के लिये कर की दर 30.6 प्रतिशत है। हांगकांग में सबसे कम 16.5 प्रतिशत की दर से कर लागू है। सिंगापुर में कॉरपोरेट कर की दर 17 प्रतिशत है। थाइलैंड और वियतनाम में 20 प्रतिशत कर लगाया जाता है। सीतारमण ने पिछले साल जुलाई में पेश बजट में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर अधिभार बढ़ा दिया था। बाद में इसे बाजार के दबाव में वापस लेना पड़ा। इसके साथ ही इक्विटी हस्तांतरण से मिलने वाले अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी लाभ को भी वापस ले लिया गया। हालांकि, बजट में अमीरों पर कर अधिभार बढ़ा दिया गया। दो से पांच करोड़ रुपये सालाना की व्यक्तिगत आय पर बढ़े अधिभार के साथ प्रभावी कर की दर 39 प्रतिशत और पांच करोड़ रुपये से अधिक की सालाना व्यक्तिगत कमाई पर बढ़े अधिभार के साथ आयकर की प्रभावी दर 42.7 प्रतिशत तक पहुंच गई। बजट में स्टार्टअप कंपनियों की मुश्किल को दूर करने के भी उपाय किये गये। स्टार्ट अप निवेश पर 'एंजल टैक्स' को समाप्त करने के उपाय किये गये।

नये साल में रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश पांच प्रतिशत बढ़कर 6.5 अरब डॉलर रहने का अनुमानः रिपोर्ट

नयी दिल्ली। एजेंसी

घरेलू रियल एस्टेट क्षेत्र में इस साल निवेश पांच प्रतिशत बढ़कर 6.5 अरब डॉलर यानी करीब 46 हजार करोड़ रुपये पर पहुंच जाने का अनुमान है। इसकी मुख्य वजह सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों की अपने कार्यस्थल के लिये बढ़ती मांग होगी। संपत्ति को लेकर परामर्श देने वाली वैश्विक कंपनी कोलियर्स ने यह अनुमान व्यक्त किया है। कंपनी के अनुसार, 2019 में विदेशी कंपनियों ने कार्यालय स्थल की व्यापक खरीद की, जिसके कारण रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश 2018 की तुलना में 8.7 प्रतिशत बढ़कर 6.2 अरब डॉलर रहा। इसमें विदेशी निवेशकों का करीब 78 प्रतिशत योगदान रहा। कोलियर्स के अनुसार, 2008 से अब तक भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में 56.6 अरब डॉलर यानी 4,10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है। रिपोर्ट में कहा गया, ''2019 में रियल एस्टेट क्षेत्र में 6.2 अरब डॉलर यानी 43,780 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। कोलियर्स को 2020 में भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में 6.5 अरब डॉलर के निवेश आने का अनुमान है।'' कंपनी का मानना है कि अगले तीन साल तक निवेशक व्यावसायिक संपत्तियों में निवेश करते रहेंगे। वर्ष 2020 में रियल एस्टेट क्षेत्र में आने वाले निवेश में व्यावसायिक दफ्तरों की करीब 40 प्रतिशत हिस्सेदारी रह सकती है। वर्ष 2019 में इनकी हिस्सेदारी 46 प्रतिशत यानी 2.8 अरब डॉलर की रही। कंपनी ने कहा कि रेरा, माल एवं सेवा कर (जीएसटी), दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) और विदेशी निवेश के प्रावधानों को आसान करने से निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है।

फार्मा सेक्टर के लिए आ सकती है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम

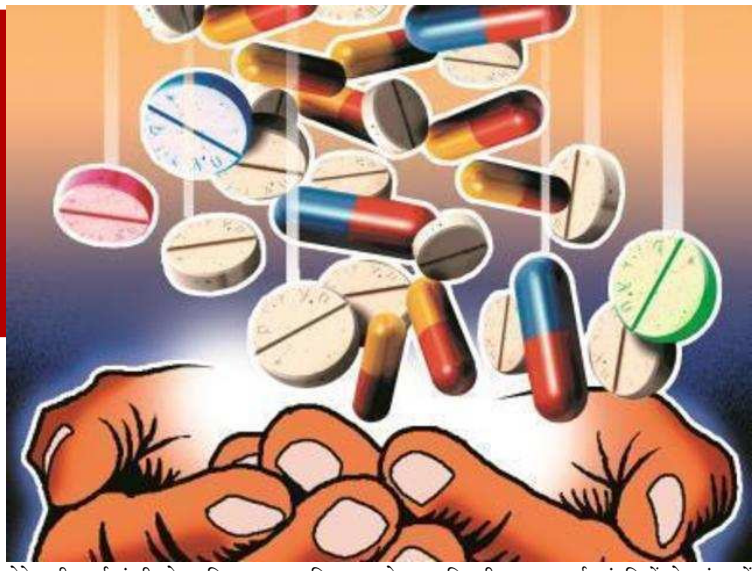

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार ऐसी फार्मास्युटिकल कंपनियों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाने जा रही है जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहती हैं। इस स्कीम के तहत सरकार 8-10 करोड़ रुपये तक के लोन पर तीन वर्ष की अवधि के लिए 6 पर्सेंट के इंटरेस्ट का बोझ उठाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल्स (DoP) अगले वर्ष फरवरी में स्कीम लॉन्च कर सकता है। स्कीम को एक सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए लागू किया जाएगा।

DoP के सेक्रेटरी पी डी वाघेला ने बताया, 'फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम (PTUAS) से ऐसी स्मॉल और मीडियम फर्मों को मदद मिलेगी जो मैन्युफैक्चरिंग में सुधार करना चाहती हैं। हमने इस बारे में इंडस्ट्री के साथ बातचीत की है। स्कीम को फरवरी में लॉन्च करन की तैयारी है।' स्कीम के लिए 2020-2022 के दौरान लगभग 300 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। स्कीम के प्रपोजल को अंतिम स्वीकृति के लिए स्टीयरिंग कमेटी के सामने रखा जाएगा। कमेटी डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों के लिए पेनाल्टी भी तय करेगी।

इस स्कीम का फायदा लेने वाली कंपनी के लिए एक्सपोर्ट से जुड़ी शर्त भी रखी गई है। इसके तहत कंपनियों को लोन लेने के 36 महीनों के अंदर लोन की रकम से अधिक एक्सपोर्ट रेवेन्यू में बढ़ोतरी करनी होगी। इसमें नाकाम रहने वाली कंपनियों पर पेनाल्टी लगेगी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन को रेगुलर लोन में बदल देगा। वाघेला ने बताया कि इस स्कीम से स्मॉल और मीडियम फार्मा एंटरप्राइजेज को फायदा होगा। ये कंपनियां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सुधार कर एक्सपोर्ट को बढ़ा सकेंगी।

लोन देने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कीम का फायदा लेने वाली फार्मा कंपनी लोन हासिल करने के दो वर्ष के अंदर WHO-GMP सर्टिफिकेशन हासिल करे। स्कीम में नई मशीनरी खरीदने की भी अनुमति होगी। एक अधिकारी ने बताया कि सरकार लंबे समय से फार्मा सेक्टर के लिए स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करने की जरूरत महसूस कर रही थी। इससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा। अधिकारी ने कहा, 'स्कीम से मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी क्योंकि WHO-GMP सर्टिफिकेशन सरकारी संस्थानों को सप्लाई करने के बहुत से टेंडर्स में हिस्सा लेने की आवश्यक शर्त होती है। स्कीम से कंपनियों को कड़े सिक्योरिटी रेगुलेशंस के साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।'

फार्मा कंपनियों के संगठनों ने इस स्कीम का स्वागत किया है। हालांकि, वह चाहते हैं कि स्कीम से एक्सपोर्ट की शर्त को हटा दिया जाए। फार्मा इंडस्ट्री के एक एग्जिक्यूटिव ने बताया कि एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन लेने में तीन-चार वर्ष लगते हैं। इस वजह से इस शर्त को हटाने की जरूरत है।

मारुति सुजुकी की घरेलू बिक्री दिसंबर में 2.4 प्रतिशत बढ़ी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की घरेलू बाजार में कार बिक्री दिसंबर महीने में 2.4 प्रतिशत बढ़ी। इसकी वजह नई वैगनआर जैसी कॉम्पैक्ट श्रेणी की कारों की मांग में वृद्धि रही। मारुति सुजुकी ने बुधवार को शेयर बाजार को बताया कि दिसंबर महीने में उसने घरेलू बाजार में 124,375 वाहनों की बिक्री की है, जो कि एक साल पहले इसी महीने 121,479 इकाइयों पर थी। निर्यात

और अन्य वास्तविक उपकरण विनिर्माता (ओईएम) को मिलाकर कंपनी की कुल बिक्री दिसंबर में 3.3 प्रतिशत बढ़कर 133,296 वाहनों पर पहुंच गई। कंपनी ने कहा कि समीक्षाधीन महीने के दौरान आल्टो समेत मिनी श्रेणी के वाहनों की बिक्री 13.6 प्रतिशत गिरकर 23,883 इकाइयों पर आ गयी। हालांकि , नई वैगनआर , स्विफ्ट , सेलेरियो और डिजायर समेत कॉम्पैक्ट श्रेणी की बिक्री करीब 28 प्रतिशत बढ़कर 65,673 इकाइयों पर पहुंच गयी। मध्यम आकार के सेडान वाहन सिआज की बिक्री 62.3 प्रतिशत बढ़कर 1,786 इकाइयों पर पहुंच गयी। जिप्सी और एर्टिगा समेत यूटिलिटी वाहनों की बिक्री 17.7 प्रतिशत बढ़कर 23,808 इकाई हो गयी। मारुति ने कहा कि अप्रैल - दिसंबर के दौरान उसकी घरेलू बिक्री करीब 17 प्रतिशत गिरकर 11 लाख इकाइयों पर आ गयी।

टोल प्लाजा पर वाहनों के Fastag से जुडे नियम किए आसान

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्र सरकार ने नेशनल हाइवे के टोल प्लाजा (Highway Toll Plaza) पर 15 दिसंबर से वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई वाहन बिना फास्टैग (Fastag) के टोल प्लाजा की फास्टैग लेन से गुजरेगा तो दोगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि, पहले एक महीने तक यानी 15 जनवरी 2020 तक हर हाइवे पर एक-चौथाई टोल बूथ पर नकद और फास्टैग दोनों से भुगतान हो सकेगा। RBI ने फास्टैग को रिचार्ज कराने के नियम आसान कर दिए हैं यानी अब आप UPI, एटीएम और क्रेडिट कार्ड्स, प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट्स से भी फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं।

RBI ने आसान किए नए नियम- RBI की ओर से 30 दिसंबर, 2019 को जारी बयान में कहा गया है कि कस्टमर्स अपने फास्टैग अकाउंट्स को पेमेंट्स के सभी ऑथराइज्ड मॉडल्स और इंस्ट्रूमेंट्स से लिंक कर सकते हैं।

इनमें यूपीआई अकाउंट्स और मोबाइल वॉलेट्स भी शामिल होंगे। यह कदम इन अकाउंट्स को रिचार्ज करने में सहूलियत बढ़ाने और फेल्ड ट्रांजैक्शंस के मामले तेजी से सुलझाने के लिए उठाया जाएगा। आरबीआई ने कहा है, 'कस्टमर्स के लिए पेमेंट के ज्यादा विकल्प देकर इस सिस्टम का दायरा बढ़ाने और सिस्टम पार्टिसिपेंट्स के बीच कॉम्पिटिशन बढ़ाने के इरादे से सभी ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम्स को अब फास्टैग्स से लिंकिंग की इजाजत होगी।

कुछ दिन पहले भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने ग्राहकों को एनईटीसी फास्टैग को भीम यूपीआई से रिचार्ज करने का विकल्प उपलब्ध कराया। एनपीसीआई ने कहा कि भीम यूपीआई आधारित मोबाइल ऐप के जरिए वाहन मालिक रास्ते में चलते-चलते भी अपने फास्टैग को रिचार्ज कर सकेंगे और उन्हें टोल प्लाजा पर लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं होगी।

नए वाहन मालिकों को FASTag के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वजह है कि ये रजिस्ट्रेशन के समय पहले से ही उपलब्ध कराए जाएंगे। ओनर को बस FASTag अकाउंट को सक्रिय और रिचार्ज करना होगा। हालांकि, आपके पास पुरानी कार है, तो आप उन बैंकों से FASTag खरीद सकते हैं जो सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (NETC) कार्यक्रम से अधिकृत हैं। इन बैंकों में सिंडिकेट बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, और इक्विटास बैंक शामिल हैं। ईएफ्ड को किसी भी प्वाइंट ऑफ सेल (POS) लोकेशन पर जाकर बैंक से ऑफलाइन खरीदा जा सकता है। हालांकि, लंबी कतारों में लगने और समय बचाने के लिए इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना आसान है। हालांकि, FASTag आवेदन करने की प्रक्रिया विभिन्न बैंकों में थोड़ी अलग होती है। फिर भी आवेदन की मुख्य बातें सभी में समान रहती हैं।

विदेशीमुद्रा भंडार 45.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 455 अरब डॉलर पर

मुंबई। एजेंसी

देश का विदेशीमुद्रा भंडार 20 दिसंबर,2019 को समाप्त सप्ताह में 45.6 करोड़ डॉलर की वृद्धि के साथ 454.948 अरब डॉलर की नयी सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच गया। इससे पिछले सप्ताहांत यह 1.070 अरब डॉलर बढ़कर 454.492 अरब डॉलर था। भारतीय रिज़र्व बैंक के जारी आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशीमुद्रा आस्तियां 31.1 करोड़ डॉलर बढ़कर 422.732 अरब डॉलर हो गयीं। सप्ताह के दौरान रिजर्व बैंक के पास आरक्षित स्वर्ण भंडार 16.4 करोड़ डॉलर बढ़कर 27.132 अरब डॉलर रहा। पर इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से पास पड़ा विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 10 लाख डॉलर घटकर 1.443 अरब डॉलर के बराबर तथा मुद्राकोष के पास पड़ी देश का आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष 1.7 करोड़ डॉलर घटकर 3.642 अरब डॉलर रह गया।

एफएसएसएआई खाद्य परीक्षण किट खरीदने के लिए 20 करोड़ रुपये खर्च करेगी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने मंगलवार को कहा कि वह देश भर में राज्य स्तर के फील्ड अधिकारियों के लिए खाद्यों का किफायती तरीके से त्वरित परीक्षण करने वाले किट या उपकरण को खरीदने के लिए 20 करोड़ रुपये खर्च करेगी। नियामक 30 रैपिड फूड टेस्टिंग किट खरीदने की मंजूरी दे चुका है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के मुख्य कार्याधिकारी पवन अग्रवाल ने कहा, ''अकेले भारत में इस तरह के किट / उपकरणों का 1,000 करोड़ रुपये का बाजार है। उन्होंने कहा , 'रैपिड फूड टेस्टिंग किट और उपकरणों का व्यापक उपयोग वर्ष 2020 में भारत के लिए स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। इससे बाजार में उपलब्ध भोजन के प्रति आम जनता का अधिक विश्वास कायम हो सकता है।''

उन्होंने एक बयान में कहा, अभी तक 30 उपकरणों पर पांच करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जो विभिन्न खाद्य उत्पादों जैसे दूध और खाद्य तेलों पर किए गए परीक्षणों के लिए त्वरित और मान्य परिणाम प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा, '' एफएसएसएआई 20 करोड़ रुपये खर्च करके त्वरित खाद्य परीक्षण किट और उपकरण खरीदेगा। ये राज्य सरकारों के माध्यम से फील्ड अधिकारियों को प्रदान किया जाएगा।'' एफएसएसएआई के अनुसार, 30 रैपिड किट में से केवल दो स्वदेशी हैं, बाकी आयात किए जाते हैं। कई शोध और वैज्ञानिक संस्थान ऐसे किट और उपकरणों के विकास में लगे हुए हैं।

इन उपकरणों को सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए हैं, ताकि राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा अपने दम पर आगे की खरीद की जा सके। इसमें कहा गया है कि एफएसएसएआई ने कई कदम उठाए हैं ताकि स्वदेशी रूप से विकसित उपकरणों को फास्ट ट्रैक आधार पर एफएसएसएआई नियमों के तहत मान्य और मंजूरी प्रदान की जा सके। अग्रवाल ने आशा व्यक्त की कि विभिन्न राज्य जीईएम पोर्टल से ऐसे किट / उपकरण भी खरीदेंगे ताकि उन्हें प्रवर्तन अधिकारियों को व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जा सके।

निर्यातकों को 1.12 लाख करोड़ रुपये का IGST रिफंड जारी किया गया: CBIC

नई दिल्ली। एजेंसी

राजस्व विभाग ने कहा कि निर्यातकों को 1.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आईजीएसटी (एकीकृत माल और सेवा कर) रिफंड किया गया है। सीमाशुल्क विभाग के पास इसके बाद सिर्फ 3,604 करोड़ रुपये का रिफंड ही लंबित रह गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि निर्यातकों को लंबित रिफंड का तुरंत भुगतान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके साथ ही 'जोखिमपूर्ण' निर्यातक इकाइयों की पहचान के लिए आंकड़ों का विश्लेषण (डेटा एनालिटिक्स) का उपयोग किया गया है।

सीबीआईसी ने कहा, 'निर्यातकों को पहले ही 1.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आईजीएसटी रिफंड का भुगतान किया जा चुका है। इस से 83,500 से अधिक निर्यातकों को लाभ हुआ है।' उसने कहा, 'यह जीएसटी के तहत रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाने के सरकार के प्रयासों को दर्शाता है।' बोर्ड ने कहा कि सिर्फ 3,604 करोड़ रुपये के रिफंड दावे ही लंबित रह गए हैं। बोर्ड ने यह भी कहा है कि 1.85 लाख निर्यातकों में से 6,421 निर्यातकों की पहचान 'जोखिम वाले' निर्यातकों के रूप में हुई है। इनमें कुछ 'स्टार निर्यातक' भी हो सकते हैं। जोखिम वाले निर्यातकों को रिफंड जारी करने से पहले केवाईसी और वैद्यीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

अब तक की प्रक्रिया में 1,241 निर्यातकों का उनके दिए गए पते पर पता नहीं लग पाया है। इनमें 8 स्टार निर्यातक भी शामिल हैं। इसके अलावा 399 निर्यातकों के मामले में प्रतिकूल वैद्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें चार स्टार निर्यातक शामिल हैं। निर्यातकों को स्टार निर्यातक का दर्जा उनकी पिछले तीन वित्त वर्ष के निर्यात प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है।

चंद्रयान-3, गगनयान... इसरो चीफ के सिवन ने बताई 2020 की पूरी योजना

बेंगलुरु। एजेंसी

इसरो चीफ के. सिवन ने नए साल के मौके पर देशवासियों के सामने इस साल के लक्ष्य और योजनाएं पेश कीं। साल 2020 में गगनयान और चंद्रयान-3 मिशन की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही इसरो चीफ ने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान के जरिए हमारी कोशिश देशवासियों के जीवन को और बेहतर बनाने की है। इसरो प्रमुख ने बताया कि दोनों महत्वपूर्ण प्रॉजेक्ट्स के लिए काफी तैयारी बीते हुए साल में ही कर ली गई है।

गगनयान के लिए अंतरिक्षयात्रियों की पहचान

सिवन ने बताया कि गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्षयात्रियों की पहचान हो गई है। इसरो चीफ ने बताया कि 2019 में गगनयान मिशन पर हमने अच्छी प्रगति हासिल की है। इस मिशन के लिए चार अंतरिक्षयात्री चुने गए हैं और जनवरी के तीसरे हफ्ते से उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गगनयान के लिए नैशनल अडवाइजरी कमिटी बनाई गई है।

चांद पर इसरो की नजर, चंद्रयान-3 के लिए तैयारी

इसरो चीफ ने बड़ी और आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि चंद्रयान-3 प्रॉजेक्ट को मंजूरी मिल गई है और इसपर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा, 'प्रॉजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। इसका कॉन्फिगरेशन चंद्रयान-2 की तरह ही होगा। इसमें भी लैंडर और रोवर होगा।' बता दें कि इसरो के चंद्रयान-2 मिशन की भारत ही नहीं दुनियाभर में काफी चर्चा हुई थी। हालांकि सिवन ने इस नए मिशन के लिए निश्चित तारीख बताने से इंकार कर दिया।

तूतीकोरिन में होगा देश का दूसरा स्पेस पोर्ट

देश के दूसरे स्पेस पोर्ट के बारे में बताते हुए सिवन ने कहा कि इसके लिए भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। दूसरा पोर्ट तमिलनाडु के तूतीकोरिन में होगा। बता दें कि आगामी एक दशक में इसरो के पिटारे में मंगल ग्रह से लेकर शनि ग्रह तक के लिए कई महत्वाकांक्षी प्रॉजेक्ट हैं जिन पर तेजी से काम चल रहा है। इसरो के गगनयान मिशन के लिए रूस मदद कर रहा है।

हरित प्रमाणपत्रों की बिक्री दिसंबर में 10 प्रतिशत घटकर 5.04 लाख यूनिट पर

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश में अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की बिक्री दिसंबर में करीब 10 प्रतिशत घटकर 5.04 लाख यूनिट रह गयी। एक साल पहले इसी महीने में यह 5.59 लाख यूनिट के लिये की गई थी। आपूर्ति कम रहने की वजह से हरित प्रमाणपत्रों की बिक्री में गिरावट आयी है। आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) और पावर एक्सचेंज आफ इंडिया (पीएक्सआईएल) दो ऐसे बिजली एक्सचेंज हैं, जो अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्रों (आरईसी) तथा बिजली का कारोबार करते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में आईईएक्स पर कुल 3.6 लाख आरईसी का कारोबार हुआ। एक साल पहले इसी महीने में यह 3.83 लाख था। वहीं पीएक्सआईएल पर आरईसी की बिक्री 1.44 लाख रही, जो दिसंबर 2018 में 1.76 लाख इकाई थी। आईईएक्स के आंकड़ों के अनुसार, सौर आरईसी तथा अन्य आरईसी दोनों की आपूर्ति कम हुई है। कम भंडारण की वजह से खरीद बोलियां बिक्री बोलियों से अधिक रही हैं। आईईएक्स में दिसंबर में आरईसी की खरीद के लिए 13.43 लाख और बिक्री के लिए 4.12 लाख बोलियां आयीं। इसी तरह पीएक्सआईएल पर 5.74 लाख खरीद और 1.49 लाख बिक्री बोलियां मिलीं। अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के तहत बिजली वितरण कंपनियां, निजी उपयोग के लिये बिजली संयंत्र लगाने वाले जैसे थोक खरीदारों को नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र खरीदने की जरूरत होती है। वे आरपीओ नियमों को पूरा करने के लिये ये प्रमाणपत्र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों से खरीद सकते हैं। बिजली वितरण कंपनियों को नवीकरणीय ऊर्जा कितनी लेनी है, इसे केंद्रीय तथा राज्य बिजली नियामक आयोग तय करते हैं। आरईसी बाजार आधारित व्यवस्था है जिसका मकसद देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और इसके बाजार को बढ़ावा देना है। यह बिजली उत्पादकों को अक्षय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित बिजली बेचने का एक वैकल्पिक स्वैच्छिक मार्ग उपलब्ध कराता है। हरित बाध्यताओं को पूरा करने के लिये संबंधित इकाइयां ये प्रमाणपत्र लेती हैं।

मेष- (21 मार्च-20 अप्रैल)

वर्ष के प्रारंभ में आपकी राशि के स्वामी अष्टमस्थ हैं। अत: आत्मविश्वास में कमी रहेगी। 7 फरवरी के बाद आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, परंतु कार्यक्षेत्र में परिश्रम की अधिकता रहेगी। माता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। 25 जनवरी के बाद शासन-सत्ता से लाभ मिलेगा, परंतु नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग भी बनेंगे। 30 मार्च से धन की स्थिति में सुधार होगा। 12 मई से 30 सितंबर के मध्य विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। यात्रा थोड़ी कष्टप्रद हो सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा। वाहन सुख में वृद्धि भी हो सकती है। 5 अक्तूबर से मन अशांत रहेगा। कार्य क्षेत्र/कारोबार में कठिनाइयां आ सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। वर्ष के अंत में संतान की ओर से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

क्या करें

- प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुड़ व भुने हुए चने का भोग हनुमान जी को लगाएं और इस भोग को बंदरों या सांड को खिला दें।
- गुरुवार प्रात: गाय को पांच केले खिलाएं।
- शनिवार को लोटे में जल भरकर उसमें चुटकीभर काले तिल व सरसों के तेल की दो बूंद डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं।

लाल किताब के उपाय

- शरीर पर शुद्ध सोना धारण करें।
- पूर्व दिशा में कूड़ेदान न रखें।
- हर मंगलवार को हनुमान की पूजा अर्चना करें।
- हल्दी युक्त दूध पिएं।
- अवैध संबंधों से दूर रहें।
- नाभि पर केसर युक्त जल लगायें।

वृष - (21 अप्रैल-20 मई)

वर्ष के प्रारंभ में आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु कार्यशीलता में कमी रहेगी। 14 जनवरी तक माता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। दिनचर्या अस्त-व्यस्त रहेगी। 15 जनवरी से परिस्थितियों में सुधार होगा। 8 फरवरी के बाद जीवनसाथी को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। 25 जनवरी से शनि की ढैय्या का प्रभाव समाप्त होगा। भाग्य में वृद्धि होगी। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे, परंतु कार्यक्षेत्र में परिवर्तन भी हो सकता है। 30 मार्च से धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। आय की स्थिति सुधरेगी। कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी। 12 मई से 30 सितंबर के मध्य नौकरी में परिवर्तन के अवसर मिल सकते हैं। 24 सितंबर से थोड़ा मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

क्या करें

- प्रतिदिन 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ कर तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े से चावल, चीनी, रोली डालकर सूर्यदेव को अर्पित करें।
- एक मुट्ठी चने की दाल बुधवार के दिन पानी में भिगो कर गुरुवार के दिन प्रात: गाय को खिलाएं।
- शनिवार हनुमान जी के चरणों में काले तिल में गुड़ मिलाकर चढ़ाएं।

लाल किताब के उपाय

- प्रत्येक शनिवार हनुमान मंदिर में मीठा प्रसाद अर्पण करें।
- सूर्यास्त पश्चात तिल के तेल का दीया जलायें।
- लावारिस कुत्तो को भोजन दें।
- सोमवार स्नानोपरांत शिव स्तोत्र का जाप करें।
- बरगद के वृक्ष तले शुद्ध घी का दीया जलाएं।

मिथुन - (21 मई-21 जून)

वर्ष के प्रारंभ में आत्मविश्वास से परिपूर्ण तो रहेंगे, परंतु धैर्यशीलता में कमी भी रहेगी। 25 जनवरी के बाद दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी। विदेश प्रवास के योग भी बन रहे हैं, परंतु शनि की ढैय्या प्रारंभ होने से कार्यों में विघ्न-बाधाएं आने से परेशानियां हो सकती हैं। संचित धन की हानि भी हो सकती है। 30 मार्च के बाद पिता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। पारिवारिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। खर्च भी बढ़ेंगे लेकिन धन की स्थिति में सुधार भी होगा। 12 मई से 30 सितंबर के मध्य किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना होगा। 24 सितम्बर के बाद से अनियोजित खर्च बढ़ेंगे। किसी मित्र से वैचारिक मतभेद भी बढ़ सकते हैं।

क्या करें

- प्रत्येक मंगलवार शाम के समय लाल कपड़े में गुड़ बांध कर हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं।
- सरसों के तेल में अपना चेहरा देखें। शनिवार को इसी तेल से सात पूए (गुलगुले) बनाकर कुत्तों को खिलाएं। बचे हुए तेल को किसी और काम में प्रयोग न करें। हर शनिवार को यही तेल प्रयोग करना होगा।

लाल किताब के उपाय

- प्रत्येक शुक्रवार काली गाय को हरा चारा खिलाएं।
- छोटी कन्याओं को बादाम भेंट करें।
- सूर्यास्त पश्चात शयन कक्ष में कर्पूर जलायें।
- हर गुरुवार पीले फूलों से विष्णु पूजन करें।
- कटे फटे जूतें न पहनें।

कर्क- (22 जून-23 जुलाई)

वर्ष के प्रारंभ में क्रोध की अधिकता रहेगी। मन अशांत रहेगा। कला व संगीत के प्रति रुझान होना चाहिए। 25 जनवरी के बाद पारिवारिक जीवन में सुधार होना चाहिए, परंतु मानसिक कठिनाइयां भी बढ़ेंगी। 30 मार्च के बाद मानसिक कठिनाइयों में कमी आनी प्रारंभ हो जाएगी। धर्म के प्रति श्रद्धाभाव रहेगा। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। 12 मई से 30 सितंबर के मध्य संतान को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। 24 सितंबर से खर्चों में कमी आएगी। आय वृद्धि के साधन विकसित होंगे। 19 नवंबर के बाद वाहन सुख में वृद्धि के योग बन रहे हैं। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। माता का सान्निध्य मिलेगा। 21 नवंबर के बाद लेखनादि बौद्धिक कार्यों से आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं।

क्या करें

- सवा पांच रत्ती का पुखराज सोने की अंगूठी में जड़वाकर दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करें।
- शनिवार सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं।
- मंगलवार के दिन रोटी में गुड़ रख कर गाय को खिलाएं।

लाल किताब के उपाय

- शयन कक्ष में नीले पर्दे/चादर का प्रयोग न करें।
- प्रत्येक शुक्रवार महालक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पण करें।
- इत्र/परफ्यूम का प्रयोग करें।
- किसी की गारंटी न लें।
- सुबह-शाम हरी घास पर नंगे पांव चलें।
- शत्रुओं को क्षमा करें।

सिंह - (24 जुलाई-22 अगस्त)

वर्ष के प्रारंभ में सम्पत्ति या भवन का लाभ हो सकता है। 8 फरवरी के उपरांत धैर्यशीलता में कमी आएगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। 25 जनवरी के बाद कुछ पुराने मित्रों से पुन: संपर्क हो सकते हैं। नौकरी में यात्रा बढ़ सकती है। विदेश यात्रा के भी अवसर मिल सकते हैं। 23 मार्च के बाद से पारिवारिक सुख में कमी आ सकती है। रहन-सहन अव्यवस्थित भी हो सकता है। 30 मार्च के उपरांत शैक्षिक कार्यों में कठिनाइयां आएंगी। 1 जुलाई से 14 सितंबर तक मन में नकारात्मक विचारों का प्रभाव हो सकता है, परंतु शैक्षिक कार्यों में सुधार आएगा। 24 सितंबर से आय में व्यवधान आ सकते हैं, परंतु राजनीति में दिलचस्पी बढ़ सकती है। 11 दिसंबर के बाद वाहन सुख की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। खान-पान के प्रति सचेत रहें।

क्या करें

- रोज 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ कर तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े से चावल, चीनी, रोली डालकर सूर्यदेव को अर्पित करें।
- प्रत्येक सोमवार के दिन चावल यथाशक्ति दान करें।
- हर गुरुवार गाय को तीन केले या तीन बेसन के लड्डू खिलाएं।

लाल किताब के उपाय

- यदा कदा मन्दिर जाएं।
- लावारिस कुत्तों को बिस्कुट आदि खाने को दें।
- नीले कपड़े पहनने से बचें।
- मित्रों को मिठाई आदि दें।
- विधवाओं की इज्जत और सहायता करें।
- खाने में काले चने शामिल करें।

कन्या- (23 अगस्त-22 सितम्बर)

वर्ष के प्रारंभ में कारोबार में परिश्रम तो अधिक रहेगा, परंतु यथानुरूप परिश्रम की फल प्राप्ति संदिग्ध रहेगी। 25 जनवरी से मानसिक शांति तो रहेगी, परंतु जीवनसाथी को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। नौकरी करनेवालों को वर्तमान नौकरी में परिवर्तन के लिए तैयार रहना होगा। 5 मई के बाद कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी दो-चार होना पड़ सकता है। 30 मार्च के उपरांत शैक्षिक एवं शोधादि कार्यों में सफलता मिलेगी। धर्म के प्रति श्रद्धाभाव बढ़ेगा। 24 अक्तूबर के बाद नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। वाहन सुख की प्राप्ति होगी। जीवनसाथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आय की स्थिति में सुधार होगा। बौद्धिक कार्यों से धनार्जन के साधन बन सकते हैं।

क्या करें

- प्रत्येक बुधवार के दिन गणेश जी के चरणों में दूर्वा घास के ग्यारह कपोल पानी से धोकर चढ़ाएं।
- प्रत्येक रविवार को यथाशक्ति गेहूं का दान करें या गाय को खिलाया करें।
- मंगलवार के दिन शाम को हनुमान जी के चरणों में लाल कपड़े में बांधकर गुड़ चढ़ाया करें।

लाल किताब के उपाय

- चींटियों को आटा और चीनी बूरा मिला कर दें।
- हर गुरुवार किसी मंदिर में 400 ग्राम चने की दाल अर्पण करें।
- नीम का पौधरोपण करें।
- हर शुक्रवार 9 छोटी कन्याओं को मिठाई/फल देकर आशीर्वाद लें।
- उच्च अधिकारियों से आदरपूर्वक व्यवहार करें।

तुला (23 सितंबर-23 अक्तूबर)

वर्ष के प्रारंभ में मानसिक शांति रहेगी। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे, परंतु 8 फरवरी तक वाणी में कठोरता का प्रभाव भी रहेगा। 25 जनवरी से पिता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। भवन सुख में वृद्धि होगी। सुख-सुविधाओं का विस्तार भी हो सकता है, परंतु स्वास्थ्य विकार बढ़ सकते हैं। विशेष रूप से खान-पान के प्रति सचेत रहें। 30 मार्च से पिता के स्वास्थ्य में सुधार होना प्रारंभ होगा, लेकिन कारोबार में व्यवधान आ सकते हैं। शैक्षिक कार्यों के परिणाम असंतोषजनक हो सकते हैं। 1 जुलाई से 14 सितंबर के मध्य कार्यक्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। 24 सितंबर के बाद नौकरी में स्थान परिवर्तन के आसार बनेंगे। परिवार का साथ मिलेगा। वर्ष के आखिर में किसी बुजुर्ग महिला से धन प्राप्ति हो सकती है।

क्या करें

- प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन यथाशक्ति पीले कपड़े में बने की दाल बांध कर मंदिर के पुजारी को दान करें।
- शनिवार के दिन प्रात: शिवलिंग पर जटा के सहित पानी वाला नारियल (ब्राउन रंग का) चढ़ाएं।
- मंगलवार के दिन रोटी में गुड़ रखकर गाय को खिलाएं।

लाल किताब के उपाय

- सोते समय अपना सिर पूर्व दिशा में रखें।
- अपने शयनकक्ष में सेंधा नमक रखें।
- योग और ध्यान का नियमित अभ्यास करें।
- चतुर्थी का व्रत रखें।
- मन्दिर जाकर अपनी गलतियों की माफी मांगें।

वृश्चिक (24 अक्तूबर-21 नवंबर)

वर्ष के प्रारंभ में आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, परंतु धैर्यशीलता में कमी भी हो सकती है। 25 जनवरी से आपकी राशि से शनि की साढ़े साती समाप्त हो रही है। कारोबार का विस्तार होगा। कोई नया कारोबार भी प्रारंभ हो सकता है। यात्रा अधिक रहेगी। खर्चों में वृद्धि होगी। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। दैनिक जीवन अव्यवस्थित रहेगा। 30 मार्च से परिवार में खुशियां आएंगी। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। आय में सुधार होगा। इस वर्ष वाहन सुख प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। वस्त्रों आदि पर खर्च बढ़ेंगे। 12 मई से 30 सितंबर का समय कठिनाईपूर्ण रहेगा। पारिवारिक समस्याएं पुन: परेशान कर सकती हैं। चिंताएं बढ़ सकती हैं। 24 सितंबर के बाद नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं।

क्या करें

- शनिवार के दिन एक ब्राउन रंग का पानी वाला नारियल जटा के साथ शिवलिंग पर चढ़ाएं।
- प्रत्येक बुधवार के दिन गाय को हरा चारा या हरी सब्जी खिलाएं।
- शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े में चावल बांधकर दान करें।

लाल किताब के उपाय

- मांसाहार का सेवन न करें।
- ससुराल पक्ष से सम्बन्धों को न बिगाड़ें।
- यथासंभव किसी से कुछ भी मुफ्त में न लें।
- माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।
- हरे रंग के कपड़े न पहनें।
- गणपति मंदिर में ऊनी कम्बल भेंट चढ़ाएं।

धनु (22 नवंबर-21 दिसंबर)

वर्ष के प्रारंभ में आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। 24 जनवरी के बाद धन की स्थिति में सुधार होगा। 30 मार्च के उपरांत नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। 2 फरवरी से धैर्यशीलता में कमी रहेगी। परिवार में आपसी मतभेद हो सकते हैं। परिवार की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। 16 मई से मन में नकारात्मकता का प्रभाव रहेगा, परंतु परिवार में शांति रहेगी। 17 अगस्त से 19 अक्तूबर के मध्य नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेंगे। 24 सितंबर के उपरांत कुछ पुराने मित्रों से पुन: संपर्क हो सकते हैं, परंतु स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी रहना चाहिए।

क्या करें

- बृहस्पतिवार के दिन गाय को 3 केले या 3 बेसन के लड्डू खिलाएं तथा प्रतिदिन 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरुवे नम:' मंत्र की एक माला जपें।
- शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
- शुक्रवार के दिन चावलों की खीर पक्षियों को खिलाएं।

लाल किताब के उपाय

- यथासम्भव नीले रंग के वस्त्र धारण न करें।
- शुद्ध चांदी की चेन धारण करें।
- भाइयों से सम्बन्ध न बिगाड़ें।
- सूर्यास्त के समय किसी मन्दिर में मीठा प्रसाद चढ़ायें।
- घर में जंग लगा चाकू/कैंची न रखें।

मकर (22 दिसंबर-19 जनवरी)

शनि की साढ़े साती आपकी राशि पर चल रही है। इस वर्ष भी साढ़े साती का प्रभाव रहेगा। 25 जनवरी को शनि मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इससे मानसिक कठिनाइयों में कमी आएगी, परंतु नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। कार्यक्षेत्र में भी परिवर्तन संभव है। पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। 8 फरवरी के बाद स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा। 30 मार्च के बाद पारिवारिक समस्याओं से निजात मिल सकती है। शैक्षिक कार्यों में सुधार आएगा। 1 जुलाई के बाद भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। घर-परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। कार्यक्षेत्र में विपरीत परिस्थितियां रहेंगी। कारोबार में कठिनाइयां आ सकती हैं। 21 नवंबर के बाद परिस्थितियों में सुधार आएगा। वर्ष के अंत में भवन या सम्पत्ति का लाभ हो सकता है।

क्या करें

- प्रतिदिन एक माल 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनये नम:' मंत्र की जपें।
- शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
- बृहस्पतिवार के दिन बेसन का मीठा परांठा बनाकर गाय को खिलाएं।

लाल किताब के उपाय

- मछलियों को आटे की गोलियां डालें।
- घर में यदाकदा गुग्गुल का धुंआ करें।
- बंदरों को गुड़-चना खिलायें।
- प्रत्येक गुरुवार केले की जड़ में थोड़ा सा जल डालें।
- रोटी बनाते समय गर्म तवे पर पानी के छींटे डालें।

कुम्भ (20 जनवरी-18 फरवरी)

25 जनवरी से आपकी राशि पर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी। खर्चों की अधिकता रहेगी। मानसिक परेशानियां रहेंगी। संचित धन में कमी भी आ सकती है। 2 फरवरी से स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। 30 मार्च के उपरांत खर्चों में कमी आएगी। घर-परिवार में धार्मिक/मांगलिक कार्य हो सकते हैं। भवन के रख-रखाव व सौंदर्यकरण के कार्यों पर खर्च बढ़ सकते हैं। 1 जुलाई से आय की स्थिति में सुधार होगा। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। 17 अगस्त के बाद कारोबार में वृद्धि के योग बन रहे हैं। शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा। वाहन की प्राप्ति हो सकती है। 24 सितंबर के बाद से माता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। दिसंबर महीने में माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। दिनचर्या व्यवस्थित बनेगी।

क्या करें

- प्रतिदिन प्रात: यह मंत्र- 'ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्द्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्' रुद्राक्ष की माला पर जपा करें।
- बुधवार के दिन गाय को हरी सब्जी या हरा चारा खिलाएं।
- हर बृहस्पतिवार को एक मुट्ठी चने की दाल डिब्बे में डालें। इकट्ठा होने पर मंदिर के पुजारी को दे दिया करें।

लाल किताब के उपाय

- महत्वपूर्ण कार्य पर जाने से पहले नाक साफ करके जाएं।
- माथे पर केसर जल का तिलक लगाएं।
- पीली बनियान धारण करें।
- मन्दिर में काली उड़द साबुत अर्पण करें।
- घर से जाले हटाएं।
- ध्यान रखें कि नल व्यर्थ न बहें।

मीन (19 फरवरी-20 मार्च)

वर्ष के प्रारंभ में आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। परिवार में सुख-शांति रहेगी। 25 जनवरी के बाद आय में वृद्धि होगी, परंतु शैक्षिक कार्यों में कठिनाई आ सकती है। 2 फरवरी से धैर्यशीलता में कमी आएगी। 30 मार्च से शैक्षिक कार्यों में सुधार आएगा। लेखनादि बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। 12 मई से नौकरी में कठिनाइयां आ सकती हैं। 30 सितंबर के बाद सुधार होगा। विदेश यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। धार्मिक कार्यों व पूजा-पाठ में व्यवधान आ सकते हैं। 21 नवंबर बाद कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेंगे। वर्ष के अंत में किसी मित्र के सहयोग से कारोबार का प्रस्ताव मिल सकता है। आय में वृद्धि होगी।

क्या करें

- सवा पांच रत्ती का पुखराज सोने की अंगूठी में जड़वाकर दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करें।
- प्रतिदिन प्रात: स्नान के बाद 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करके, तांबे के लोटे में जल भर कर उसमें थोड़े से चावल, चीनी या गुड़ तथा रोली डालकर जल की धार बना कर सूर्यदेव की तरफ मुंह करके जल अर्पित करें।

लाल किताब के उपाय

- स्नानोपरांत उगते सूरज को जल अर्पण करें।
- लाल रंग का रूमाल अपने पास रखें।
- प्रत्येक शनिवार दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करें।
- सुबह हरी घास पर पानी डालें।
- शराब का सेवन न करें।
- गुलाब की महक वाली अगरबत्ती जलाएं।

नए साल में एक लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाएगी सरकार

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

इस साल प्याज की आसमान छूती कीमतों को देखते हुए सरकार अभी से इस तैयारी में जुट गई है कि अगले साल हालात ऐसे ना बनें। केंद्र सरकार ने प्याज के बफर स्टॉक को करीब दोगुना करते हुए एक लाख टन बनाने का निर्णय किया है। वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि सरकार ने चालू वर्ष में प्याज का 56,000 टन का बफर स्टॉक तैयार किया था, लेकिन यह बढ़ती कीमत को रोकने में नाकाम रहा। प्याज के दाम अभी भी ज्यादातर शहरों में 100 रुपये किलो से ऊपर चल रहे हैं।

परिणामस्वरूप, सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की एमएमटीसी के जरिये प्याज आयात के लिये मजबूर होना पड़ा है। इससे जुड़े अधिकारी ने कहा, 'गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाल में मंत्री समूह की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। यह निर्णय किया गया है कि अगले साल के लिये करीब एक लाख टन का बफर स्टॉक तैयार किया जाएगा।' सरकार की तरफ से बफर स्टॉक रखने वाली संस्था नाफेड (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ) अगले साल यह जिम्मेदारी निभाएगा।

नाफेड मार्च-जुलाई के दौरान रबी मौसम में पैदा होने वाले प्याज की खरीदारी करेगा। इस प्याज का जीवनकाल अधिक होता है। खरीफ मौसम में पैदावार क्षेत्रों में देर तक मानसूनी बारिश और बाद में बेमौसम भारी बारिश के कारण इस साल प्याज के उत्पादन में 26 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसका असर कीमत पर पड़ा है।

सरकार ने प्याज के दाम में तेजी पर अंकुश लगाने के लिये कई कदम उठाए हैं। इसमें निर्यात पर पाबंदी, व्यापारियों पर भंडार सीमा के अलावा बफर स्टॉक और आयात के जरिये सस्ती दर पर प्याज की बिक्री शामिल हैं। सरकार के पास जो बफर स्टॉक था, वह समाप्त हो चुका हैं। सस्ती दर पर ग्राहकों को उपलब्ध कराने के लिये अब आयातित प्याज की बिक्री की जा रही है।

अभी ज्यादातर शहरों में प्याज की कीमतें 100 रुपये किलो के आसपास है। ईटानगर में प्याज की कीमत 150 रुपये किलो है। सरकार ने कीमतों पर लगाम के लिए विदेशों से प्याज खरीदा है। लगभग 1,160 टन प्याज भारत पहुंच चुका है। अगले 3-4 दिनों में अतिरिक्त 10,560 टन आयात की खेप आने की उम्मीद है। तुर्की, मिस्र और अफगानिस्तान से प्याज आयात किए गए हैं। अब तक सरकार करीब 50 हजार टन प्याज का ऑर्डर दे चुकी है।

केंद्र सरकार ने क्रुड पॉम के साथ रिफांइड तेलों के आयात शुल्क में की कटौती

नई दिल्ली। एजेंसी

विदेशी बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में चल रही तेजी के कारण केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों के आयात शुल्क में कटौती की है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार क्रुड पॉम तेल के आयात पर शुल्क को 40 फीसदी से घटाकर 37.5 फीसदी और रिफाइंड तेल के आयात पर शुल्क को 50 फीसदी से घटाकर 45 फीसदी कर दिया है।

मलेशिया और इंडोनेशिया से पाम तेल का आयात महंगा होने के कारण घरेलू बाजार में भी खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी आई है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) ने हाल ही में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर खाद्य तेलों के आयात शुल्क में कमी नहीं करनी की मांग की थी। एसईए के कार्यकारी निदेशक डॉ. बीवी मेहता के अनुसार अंतराष्ट्रीय बाजार से आयात महंगा होने के कारण घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इससे देश के किसानों को तिलहनों का ऊंचा भाव मिल रहा है, जिससे वे तिलहनों की खेती करने को लेकर उत्साहित होंगे।

खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देना होगा

उन्होंने कहा कि हमें अगर खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनना है तो किसानों को प्रोत्साहन देना ही पड़ेगा जोकि उन्हें उनकी फसलों का बेहतर व लाभकारी दाम दिलाकर किया जा सकता है। भारत दुनिया का दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक है जो खाद्य तेल की अपनी जरूरतों के अधिकांश हिस्से की पूर्ति आयात से करता है। बेमौसम बारिश और बाढ़ के कारण खरीफ सीजन में सोयाबीन की फसल को नुकसान हुआ था, जिस कारण उत्पादन अनुमान में कमी आई।

आयातित खाद्य तेलों की कीमतों में आई तेजी

अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में खाद्य तेलों की कीमतों में भारी तेजी दर्ज की गई है। भारतीय बंदरगाह पर आरबीडी पामोलीन का भाव नवंबर 2019 में बढ़कर औसतन 663 डॉलर प्रति टन रहा, जबकि अक्टूबर में इसका भाव 567 डॉलर प्रति टन था। इसी तरह से क्रुड पाम तेल का भाव नवंबर में बढ़कर 636 डॉलर प्रति टन हो गया जबकि अक्टूबर में इसका दाम औसतन 541 डॉलर प्रति टन था। क्रुड सोया तेल के भाव इस दौरान 722 डॉलर से बढ़कर 763 डॉलर प्रति टन हो गए। एसईए के अनुसार तेल वर्ष 2018-19 (अक्टूबर-18 से नवंबर-19) के दौरान खाद्य एवं अखाद्य तेलों का आयात बढ़कर 149.13 लाख टन का हुआ, जोकि इसके पिछले साल के 145.16 लाख टन से ज्यादा है। देश में तेल वर्ष 2016-17 में रिकार्ड 150.77 लाख टन खाद्य एवं अखाद्य तेलों का आयात हुआ था।

रबी तिलहन की बुआई घटी

रबी तिलहन की बुआई चालू सीजन में 74.12 लाख हेक्टेयर में ही हुई है जबकि पिछले साल इस समय तक इनकी बुआई 74.72 लाख हेक्टेयर हो चुकी थी। रबी तिलहन की प्रमुख फसल सरसों की बुआई 65.68 लाख हेक्टेयर में ही हुई है जबकि पिछले साल की समान अवधि में इसकी बुआई 66.40 लाख हेक्टेयर में हो चुकी थी। मूंगफली की बुआई 3.56 लाख हेक्टेयर में और अलसी की बुआई 2.91 लाख हेक्टेयर तथा सनफ्लावर की बुआई 84 हजार हेक्टेयर में हुई है। पिछले साल इस समय तक मूंगफली की बुआई 3.30 और असली की बुआई 3.08 लाख हेक्टेयर में ही हुई थी।

Jawa Perak की बुकिंग शुरू, 10 हजार में करें बुक

नई दिल्ली। एजेंसी

Jawa Motorcycles की बॉबर स्टाइल बाइक Jawa Perak की बुकिंग आज (1 जनवरी) शाम 6 बजे शुरू होगी। कंपनी की वेबसाइट और डीलरशिप पर इस बाइक को 10 हजार रुपये में बुक कर सकते हैं। बुकिंग अमाउंट रिफंडेबल है। इसकी डिलिवरी 2 अप्रैल 2020 को शुरू होगी। जावा पेरक नवंबर 2019 को लॉन्च की गई थी। इसकी एक्स शोरूम कीमत 1.95 लाख रुपये है। जावा पेरक फिलहाल देश की सबसे सस्ती फैक्ट्री-मेड (कंपनी की बनाई गई) बॉबर बाइक है। इसका लुक काफी अट्रैक्टिव है। बाइक में दिए गए राउंड हेडलैम्प, सिंगल सीट, ब्लैक वायर स्पोक वील्ज, बार-एंड मिरर्स, छोटे फेंडर्स और स्लैश-कट एग्जॉस्ट इसे क्लासिक बॉबर बाइक का लुक देते हैं। पेरक में इंटीग्रेटेड टेललाइट के साथ फ्लोटिंग सिंगल सीट स्टैंडर्ड दी गई है, जो इसे कम्प्लीट बॉबर लुक देती है। हालांकि, बाइक में पिछली सीट का भी ऑप्शन है। इसकी सीट हाइट 750mm, वील बेस 1485mm और इसका वजन 179 किलोग्राम है। बाइक की फ्यूल टैंक कपैसिटी 14 लीटर है।

अगले साल सभी जिलों में खुलेंगे कॉमन सर्विस सेंटर!

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में आधार कार्ड के लिए नामांकन और अपडेशन की खातिर अगले साल 700 नए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) खोले जाएंगे। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। इन डिजिटल किऑस्क को सरकार चलाती है। ये ज्यादातर दूरदराज के इलाकों में मौजूद हैं। दो साल पहले सुरक्षा से जुड़ी समस्या के कारण इन्हें सेवाएं देने से रोक दिया गया था। एएए ई-गवर्नेंस सर्विसेज के सीईओ दिनेश त्यागी ने कहा कि यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने इन सेवाओं की बहाली वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ळध्ध्ध् आधार प्रोग्राम चलाती है। हालांकि फिलहाल सेवाएं केवल एएए के अपने कार्यालयों पर दी जाएंगी। उनकी तरफ से मैनेज होने वाले 3,60,000 सेंटर्स पर ये सर्विस नहीं मिलेंगी। अभी हर राज्य में एक एएए ऑफिस है। सरकार सभी जिलों में एक नया सेंटर खोलने की तैयारी कर रही है। त्यागी ने कहा, 'इन कार्यालयों को आधार सेवा केंद्र जैसी सुविधाएं देने और विशेष पहचान संख्या के लिए सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिहाज से तैयार किया जाएगा।'

उन्होंने बताया कि इन केंद्रों को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड आईटी के अंतर्गत आने वाली CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज में कार्यरत अधिकारी चलाएंगे न कि ग्रामीण स्तर के आंत्रप्रन्योर की ओर से चलाए जाने वाले स्वतंत्र नेटवर्क के तहत आने वाले एएए। ळध्ध्ध् ने ये सेवाएं देने की खातिर योग्यता होने के लिए टर्मिनल्स और व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होने जैसी कुछ शर्तें तय की हैं। उन्होंने कहा, 'ये शर्तें कुछ क्षेत्रों में व्यावहारिक हो सकती हैं, कुछ में नहीं। इसलिए हम इस पर UIDAI के साथ चर्चा कर रहे हैं।' एएए का खासकर गांवों में व्यापक नेटवर्क तैयार हो गया था। इस लिए उनके जरिए आधार संख्या के लिए नामांकन और अपडेशन का एएए को फायदा मिला है। उनके लिए भी ये सेवाएं कमाई का बड़ा जरिया बन गई थीं।

सरकार के फैसले से खुश हुए विदेशी निवेशक

2019 में किया रेकॉर्ड इन्वेस्टमेंट

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय शेयर बाजार में संस्थागत निवेशकों (इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स) ने साल 2019 में रेकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया है। एक अनैलेसिस में पाया है कि डमेस्टिक इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरन इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 2019 में कुल मिलाकर 1.43 लाख करोड़ रुपये निवेश किए। यह पिछले 15 वर्षों सालों में सबसे ज्यादा है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए फैसलों का निवेशकों ने स्वागत किया है। बजट में इझ्र पर बढ़ाए गए सरचार्ज को निर्मला सीतारमण ने अगस्त में वापस ले लिया था, जिसका असर साफ दिख रहा है।

FPI की हिस्सेदारी दो तिहाई

फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इस रकम में से करीब दो तिहाई हिस्सा निवेश किया। बाकी पैसा लोकल फंड्स ने निवेश किया। पिछले 15 वर्षों में संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में सालाना औसतन 75076 करोड़ रुपये का निवेश किया है। 2019 में संस्थागत निवेशकों ने इस औसत का लगभग दोगुना पैसा निवेश किया।

15 सालों में अब तक 162 अरब डॉलर का निवेश

इझ्र और अ्रझ्र पिछले 15 में से छह वर्षों में नेट बायर रहे यानी उनका कुल निवेश उनकी ओर से की गई कुल बिकवाली से ज्यादा रहा। इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पिछले 15 वर्षों में कुल मिलाकर करीब 162 अरब डॉलर भारतीय शेयर बाजार में निवेश किए हैं। इस दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों और देसी संस्थागत निवेशकों के निवेश का अनुपात 2.55 रहा।

देसी निवेशकों का निवेश बढ़ा

संस्थागत निवेशकों के पास सितंबर 2019 के अंत में बीएसई 500 कंपनियों की टोटल इक्विटी का करीब एक तिहाई हिस्सा था। 2019 में संस्थागत निवेश भारतीय शेयर बाजार के कुल पूंजीकरण का करीब एक प्रतिशत रहा। यह पिछले पांच साल के औसत के आसपास रहा, जिस दौरान देसी निवेशकों की ओर से निवेश बढ़ा। इस निवेश में बढ़ोतरी सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण आई।

DII का हिस्सा सितंबर तिमाही में 14.40 फीसदी

बीएसई 500 कंपनियों में डमेस्टिक इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हिस्सा सितंबर तिमाही में 14.4 प्रतिशत के साथ रेकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। लोकल मनी का दमखम बढ़ने से डमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम के प्रतिशत का अंतर काफी घटा। 2019 में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम विदेशी संस्थागत निवेशकों के ट्रेडिंग वॉल्यूम के करीब आधे पर रहा।

एएइ का असेट मैनेजमेंट नवंबर में 3.12 लाख करोड़

लोकल म्यूचुअल फंड्स के लिए एसआईपी का असेट अंडर मैनेजमेंट नवंबर 2019 में 3.12 लाख करोड़ रुपये पर रहा, जो मार्च 2019 में 2.66 लाख करोड़ रुपये पर था। यह आंकड़ा असोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया का है।

देर तक टिकने वाले शेयर का आंकड़ा बढ़ रहा है

एसआईपी बुक बढ़ने से पता चल रहा है कि भारतीय शेयरों में देर तक टिकने वाली रकम का आंकड़ा बढ़ रहा है। इसी तरह 2019 में फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के ळ्ठ में लॉन्ग टर्म फॉरन फंड्स का हिस्सा बढ़ा। नवंबर 2019 में देर तक टिके रहने वाले फॉरन फंड्स का प्रतिशत बढ़कर 21.41ज्ञ पर पहुंच गया। इस तरह पिछले दो वर्षों में इसमें 333 बेसिस प्वाइंट्स की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

लॉन्ग टर्म में बाजार की मजबूती बढ़ेगी

लॉन्ग टर्म इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बढ़ती हिस्सेदारी से भारतीय बाजार की मजबूती बढ़ सकती है और करंसी में वोलैटिलिटी रहने और रिस्क से बचने के माहौल में बिकवाली का दबाव घट सकता है।

भारत, पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान किया

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत और पाकिस्तान ने 29 वर्षों से चली आ रही परंपरा को जारी रखते हुए एक द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत बुधवार को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान किया। यह व्यवस्था दोनों देशों को एक-दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने से रोकता है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने 'भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों के खिलाफ हमले पर रोक के समझौते' के तहत आने वाले परमाणु प्रतिष्ठानों और केंद्रों की सूची का आदान-प्रदान किया। यह नयी दिल्ली और इस्लामाबाद में कूटनीतिक माध्यमों के जरिए किया गया।दोनों देशों के बीच कश्मीर मुद्दे को लेकर चल रहे कूटनीतिक तनाव के मद्देजनर सूची का आदान-प्रदान किया गया। इस समझौते पर 31 दिसंबर 1988 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ।इस समझौते के तहत दोनों देशों के लिए हर साल एक जनवरी को एक-दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों और केंद्रों की सूचना देना अनिवार्य है। पहली बार एक जनवरी 1992 को सूची का आदान-प्रदान किया गया था और यह लगातार 29वां साल है।

नए साल का नया नियम, याद रखें भारतीय रेल का 139 सेवा नंबर

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

नए साल का आगाज हो चुका है। वहीं भारतीय रेल भी अपने करोड़ों यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए-नए बदलाव करता रहता है। भारतीय रेल सर्विसेज बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही है। इसी के साथ यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल ने हेल्पलाइन नंबर 139 को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब विभिन्न सेवाओं के लिए अब सिर्फ इसी नंबर पर कॉल किया जा सकेगा। 1 जनवरी से इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी है।

पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए कहा कि रेलवे की विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों को एकीकृत कर 139 में बदल दिया गया है, यह नंबर इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस पर आधारित है। यह व्यवस्था 1 जनवरी से लागू की जा रही है, इसके शुरू होने पर यात्रियों को सहायता के लिए अलग अलग नंबरों के स्थान पर सिर्फ एक हेल्पलाइन नंबर 139 को याद रखना होगा।

जानकारी के अनुसार भारतीय रेल रेलवे में यात्री सुविधा और सेवा के कई नंबर जारी थे. जिससे कई बार यात्री अथवा जरूरतमंद विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की सर्विस को लेकर कन्फ्यूज हो जाते थे। जिसको देखते हुए 1 जनवरी से भारतीय रेल के अनेक हेल्पलाइन नंबर की बजाय सिर्फ 139 नंबर जारी किया है। अब आप सिर्फ 139 नंबर का इस्तेमाल कर रेलवे से जुड़ी हर समस्या का निपटारा कर सकते हैं। दरअसल, भारतीय रेल ने अब 139 सेवा नंबर को एकीकृत रेलवे हेल्पलाइन में तब्दील कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये नंबर इंटरैक्टिव वाइस रिस्पांस सिस्टम पर आधारित है. ऐसे में अब यात्रियों को अलग-अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है।

किराए में बढ़ोतरी

वहीं नया साल के आगाज के साथ इंडियन रेलवे ने किराए में बढ़ोतरी कर लोगों को तगड़ा झटका दिया है। वहीं नया रेल किराया एक जनवरी से लागू होगा. किराये में बढ़ोतरी का बड़ा असर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर होगा. रेलवे ने 4 पैसे प्रति किलोमीटर तक यात्री किराए में बढ़ोतरी की है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।